और पुनरुद्धार प्लान के अंतिम रूप देने में लंबित होने के कारण कार्यशील पूंजी की बाधा इत्यादि की वजह से निवेश की समय पर आपूर्ति होने में बाधा होना शामिल है।

विवरण

भारी उद्योग विभाग के तहत सरकारी क्षेत्र के उन उपक्रमों के नाम जिनके पुनरुद्धार प्लान सरकार/बीआईएफआर के विचाराधीन हैं

क्रम संख्या	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के नाम
1.	हिन्दुस्तान फोटो फिल्मस मैन्यु० कंपनी लिमिटेड
2.	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड*
3.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5.	प्रागा टूल्स लिमिटेड
6.	नागालैण्ड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड
7.	नेपा लिमिटेड*
8.	साइकिल कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9.	नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
10.	माण्डया नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड

* सरकार ने इन उपक्रमों में पुनरुद्धार/पुनर्संरचना प्लान को पहले ही अनुमोदित कर दिया है जो बीआईएफआर की अंतिम सिफारिशों की प्रतीक्षा कर रहे है।

Modernisation of Industrial clusters

2060. SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:
SHRI NILOTPAL BASU:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the amount sanctioned and disbursed by Departments of SSI for technology development and modernisation of industrial clusters in India under UNIDO scheme; and

(b) the cluster in West Bengal which has been identified for modernisation and the fund allocated to it?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) The UNIDO cluster development programme in India is a part of a global programme funded by the Italian Ministry of Foreign Affairs and executed by UNIDO. The programme activities started in India in May 1996 and completion is envisaged in December 2000. Besides the activities (seminars/workshops etc.) aiming at transferring the "Cluster development approach" at the national and state level, the programme has developed pilot projects in four clusters, namely Hand-printed Textiles of Jaipur (Rajasthan), Food Industry of Pune (Maharashtra), Cotton Hosiery of Tirupur (Tamil Nadu) and Woollen Knitwear of Ludhiana (Punjab). The amount spent on the programme in India till 31st December, 1998 is approximately US $ 350,000.

(b) There is no cluster in West Bengal that has been identified for modernisation under the programme so far.

लघु उद्योगों पर मंदी का प्रभाव

2061. **श्री ओम प्रकाश कोहली:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों पर मंदी का बहुत बुरा असर पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान 30 प्रतिशत है;

(ग) क्या फेडरेशन ऑफ दि एसोसिएशन्स ऑफ स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष द्वारा लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता की मांग की गई है ताकि ऐसे उद्योग देश की अर्थव्यवस्था में अपनी भूमिका का निर्वाह करने में समर्थ बने रहे; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): (क) लघु उद्योग क्षेत्र में 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के वर्षों में उत्पादन की विकास दर क्रमशः 11.40%, 11.32% और 8.43% रही है। इससे प्रतीत होता है कि लघु उद्योग मंदी के कारण बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने लघु उद्योगों के लिए वित्तीय सहायता के प्रवाह को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय बजट 1999-2000 में कई प्रावधान किये हैं। ये प्रावधान नीचे दर्शाए गए हैं:—

(1) नई ऋण बीमा योजना की शुरूआत।

(2) मिश्रित ऋण योजना के तहत मिश्रित ऋण की सीमा 2 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये करना।

(3) 20 प्रतिशत की कारोबार मानक अपेक्षा के तहत कार्यशील पूंजी का निर्धारण करने के लिए कोरोबार सीमा को 4 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपया करना।

(4) गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए अति लघु क्षेत्र को बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण देने की सीमा के अंदर शामिल किया जा रहा है।

(5) खाद्य तथा कृषि प्रसंस्करण उद्योग को बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र के लिए ऋण की परिधि में लाना

उपर्युक्त के अलावा, केन्द्रीय बजट 1999-2000 में कई राजकोषीय प्रोत्साहन भी दिये गये हैं। वे प्रोत्साहन नीचे दर्शाये गए हैं:—

(1) 100 प्रतिशत मोडवेट ऋण की बहाली।

(2) ग्रामीण क्षेत्र में स्थित एककों को ब्रांड-युक्त वस्तुओं के लिए उत्पाद शुल्क में छूट।

(3) सामान्य उत्पाद शुल्क छूट योजना में सूती धागे को शामिल करना।

(4) 1.4.1999 से कास्मेटिक, टालेट उत्पादन, वातानुकूल, रेफ्रिजरेशन उपकरण और इनके पुर्जों के लिए एस०एस०आई० छूट योजना में संशोधन।

(5) चमकदार टाइलों के मुद्रण के लघु छोटे कार्यों में लगे कामगारों को शुल्कों में छूट देनी।

(6) लघु औद्योगिक इकाइयों को मासिक आधार पर उत्पाद शुल्क अदायगी की अनुमति दिया जाना।

Foreign Direct Investment

2062. SHRI VAYALAR RAVI: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether the Foreign Direct Investment increased in 1998;

(b) if so, the details of FDI for the last five years and the area of investment; and

(c) the total applications pending for clearance and the total amount involved?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) and (b) Sir, the details of Foreign Direct Investment made in the last five years from January, 1994 to December, 1998 are as under:—

Amount in Rs. crores

Year	Total FDI made (excluding GDR)
1994	2981.85
1995	6370.15
1996	8744.37
1997	12989.27
1998	13269.21
TOTAL (1994—1998)	44354.85

From Jan. 1994 till Dec. 1998, 55.81% of the total investment has gone into 10 sectors. The list of these investments, Sector-wise is enclosed as statement(*See below*). Remaining 44.19% has gone to other industrial sectors.

(c) Sir, Foreign Direct Investment applications are disposed of in a time bound manner, which is a continuous process.